

राहुल के बयान पर बवाल

कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार बनाने के सार विकल्प खुले बता कर एक तरफ गठबंधन राजनीति की हकीकत बयान कर दी है तो दूसरी तरफ पछाड़ खा रहे, कुछेक सहयोगी दलों को नाराज भी कर दिया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तारीफ और जयललिता व वाममोर्चा से समर्थन की उम्मीद जता कर जहां राहुल गांधी ने अभी भी संप्रग के साथ चल रहे लालू प्रसाद और रामविलास पासवान को भड़काने और बयान देने को मजबूर कर दिया, वहीं वाममोर्चा जैसे कट्टर शत्रु के करीब आने की संभावना जताकर ममता बनर्जी के लिए आंखे तररने की स्थिति पैदा कर दी है। उधर तमिलनाडु में सोनिया गांधी की रैली रद्द किए जाने पर कांग्रेस द्रमुक संबंधों पर तमाम आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं।



हालांकि मोइली से लेकर अश्विनी कुमार तक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उनके इस बयान पर सहयोगी दलों को समझाने और शांत करने में जुट गए हैं और शायद शांत कर भी लिया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी ने चुनाव के बाद दिए जाने वाले इस रणनीतिक बयान को चुनाव के पहले क्यों दिया?

क्या यह समझदारी भरा बयान था या जल्दबाजी में दिया गया

नासमझी भरा बयान? मूलतः इस बयान का अर्थ है कि कांग्रेस भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को प्रतिपक्षी पार्टी नहीं मानती। कमोबेश यही स्थिति भाजपा की भी है बस फर्क इतना है कि उसे वाममोर्चा का समर्थन कभी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए सार विकल्प खुले रखने की बात कह कर राहुल गांधी यही बताना भी चाहते थे कि कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लिए भाजपा से ज्यादा विकल्प खुले हैं और वाममोर्चा कांग्रेस का वैसा दुश्मन नहीं है जैसा कि भाजपा का।

इस बयान के माध्यम से राहुल गांधी सरकार के निर्माण में अपनी बढ़ती रणनीतिक भूमिका को तो रेखांकित कर ही रहे थे साथ ही भाजपा और राजग के उस प्रचार की हवा भी निकाल रहे थे जो उसने तीसर चरण के मतदान के बाद बड़े जोर-शोर से चला रखा है। दुलमुल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चल रहे भाजपा के दावे को खारिज कर राहुल गांधी ने कांग्रेस का दावा मजबूत कर दिया है। इस बयान का तात्कालिक तौर पर इतना ही मतलब है। आगे की स्थितियां जैसा कि प्रियंका गांधी ने इशारा किया है कि 16 मई के चुनाव परिणाम तय करेंगे।

नीतीश पर टिप्पणी भारी पड़ी मोइली को

नई दिल्ली। एम वीरप्पा मोइली को कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उन्होंने आश्चर्यजनक तरीके से जद यू नेता नीतीश कुमार की आलोचना की थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उनकी जगह कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी को पार्टी के मीडिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह पहले इस जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने एक और प्रवक्ता अश्विनी कुमार की भी उनके पद से छुट्टी कर दी है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी उनके काम से खुश नहीं थी। इस कारण उनके खिलाफ ऐसा कदम उठाया गया।

ऐसा समझा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणियों से पार्टी आला कमान उनसे नाराज था। उनके हटाए जाने को इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि हाल में ही पार्टी ने ता राहुल गांधी ने नीतीश की तारीफ कर उन्हें लुभाने की कोशिश की थी। मोइली ने कहा था कि वे नहीं मानते कि कांग्रेस स नीतीश कुमार को हीरो बनाने जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने भाजपा से नाता रखा है और उसे बनाए हुए हैं। सांप्रदायिकता के कारण



उनकी धर्मनिरपेक्ष साख दूषित हुई है।

कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख के पद से उनकी छुट्टी किए जाने के पार्टी के फैसले के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने बेंगलूर से सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने द्विवेदी को प्रभार सौंप दिया है क्योंकि वह 17 मई तक कर्नाटक में रहेंगे। मोइली कर्नाटक के चिकबल्लापुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस मीडिया प्रमुख ने कल रेल मंत्री लालू प्रसाद और लोजपा प्रमुख राम विलास पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक का बहिष्कार करने संबंधी रपटों के मद्देनजर आड़े हाथ लिया था। बाद में उन्होंने अपना ख नरम

करते हुए कहा था कि वे संप्रग का हिस्सा हैं और संप्रग सरकार में वापस लौटेंगे। सूत्रों ने बताया कि मोइली इससे पहलले भी अपनी हदे पार कर चुके हैं। इसकी वजह से पार्टी को विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ा है। मोइली पिछले कुछ महीने से पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने पिछले महीने उस समय द्विवेदी को प्रभार सौंप दिया था जब वह कर्नाटक गए थे। उन्होंने पिछले हफ्ते ही दोबारा यह जिम्मेदारी संभाली थी।

कालेधन के हमाम में...



पहले पेज से जारी... यह भी हो सकता है, जो तथ्य मिले हैं उनसे यह कहा जा सकता है कि इस बहस का बीजारोपण दिसंबर 2008 में हो गया था. हुआ यह था कि वाशिंगटन में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी नामक संस्था ने एक प्रोग्राम बनाया. उसके तहत दुनिया भर में काले धन की आवाजाही पर अध्ययन कराया गया. उसका नाम दिया गया ग्लोबल फाइनेंसियल इंटीग्रीटी प्रोग्राम. उसकी जब रिपोर्ट आई तो कोहराम मच गया. उससे यह बात सामने आई कि 2002-2006 के दौरान हर साल भारत से 22.7 अरब डॉलर चोरी छिपे बाहर जाता रहा है. साफ है कि यह एक कड़ी को उजागर करता है. उससे हांडी के पूरे चावल का हाल जाना जा सकता है. यह बात अलग है कि काली कमाई एक मानवीय रोग है जो सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि उस रिपोर्ट के मुताबिक 160 देशों में है. जी-20 शिखर सम्मेलन से जो दूसरी बात उजागर हुई है वह सरकार के इरादे पर गंभीर सवालिया निशान लगा देती है. मनमोहन सरकार ने उस करार के अनुसमर्थन में पहला कदम भी नहीं उठाया है. क्या सिर्फ इस कारण बहस छिड़ी है. जानकारों का कहना है कि बहस तो सिर्फ एलजीटी बैंक लिचेंस्टाइन में जिनके खाते हैं उस पर छिड़ी है. जिसकी सूची पी. चिदंबरम के पास है. वह उन्हें 18 मार्च को मिल गई थी. ऐसी कितनी सूचियां तमाम विदेशी बैंकों से निकलेंगी यह गहरी छानबीन से ही सामने आएगा. सवाल असली तो यह है कि क्या इस राजनीतिक व्यवस्था में वह छानबीन हो पाएगी?

चुनावी समर में मुद्दे के तौर पर विदेशों में जमा धन लोगों की जुबान पर चढ़ गया है. थोड़े ही लोग जानते हैं और वे विशेषज्ञ माने जाते हैं कि विदेशों में जमा धन मोटे तौर पर तीन तरह का है पहले प्रकार में औद्योगिक घराने आते हैं. जिन्होंने कर चोरी से रकम बचायी है और जमा कराई है. दूसरे वे हैं जो मंत्री और अफसर रहे हैं या हैं और उन्होंने तमाम सौदों में दलाली की है जिसे विदेशों में सुरक्षित रखा है. तीसरे वे हैं जो अपराध की दुनिया में राज करते हैं और तमात तरह की उगाही से इतना मालामाल हो गये हैं कि उन्हें अपनी रकम हवाला के जरिये बाहर भेजना जरूरी हो जाता है. अफसोस इस बात का है कि चुनाव के समय यह सवाल भले ही लोगों के मन को मथे पर इस कड़वी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इस राजनीतिक व्यवस्था में जो राज कर रहे हैं उनका ही पैसा विदेशों में जमा है. वे क्या उसे वापस लाने देंगे?

लालू-पासवान की चिढ़

पांचवें चरण के मतदान से पहले ही भावी गठबंधनों के लिए जोड़-तोड़ का सीधा-सा मतलब यह है कि कोई भी दल या गठबंधन चुनाव परिणामों को लेकर आश्वस्त नहीं है। एक खेमा दूसरे के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। तरह-तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। अपने समर्थन के लिए अजीब-अजीब-सी मांगें पेश की जा रही हैं। राजनीतिक परिदृश्य कुछ ऐसा बन रहा है कि कुछ भी असंभव नहीं है। जो वाम दल तक कांग्रेस स की भर्त्सना करते नहीं थक रहे थे, आज उसके साथ फिर सत्ता की संभावनाएं टटोल रहे हैं। यही बात कांग्रेस पर भी लागू होती है। नीतीश कुमार, जयललिता और मायावती की तरफ हर कोई डोरे डाल रहा

है। ऐसे मधुर वातावरण में लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान का अलग-थलग पड़ना कुछ अस्वाभाविक लग रहा है। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं गए। क्योंकि वे राहुल गांधी द्वारा खुले आम नीतीश कुमार की तारीफ किए जाने से नाराज चल रहे हैं। हालांकि हर निजाम में अपनी जगह तलाश लेनेवाले पासवान ने अपनी राजनीतिक व्यस्तता के चलते कैबिनेट में न जा पाने की सफाई दी है और यह भी कहा है कि वे संप्रग में बने हुए हैं, लेकिन राहुल के कथन पर अपनी नाराजगी का इजहार उन्होंने भी किया है। इन दो क्षत्रपों की नाराजगी पर जैसे कांग्रेस को भी पुराने जख्म कुरेदने का मौका मिल गया है। वीरप्पा मोइली ने पलटवार करते हुए कहा है कि लालू और पासवान

ने बिहार चुनाव में कांग्रेस के लिए तीन सीटें छोड़कर एक राष्ट्रीय पार्टी का अपमान किया, इसलिए नाराज तो कांग्रेस को होना चाहिए। मोइली गलत नहीं कह रहे। वास्तव में लालू और पासवान, जो पिछले चुनाव तक एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं देख सकते थे, अचानक चुनाव के मौके पर कैसे एक हो गए और बिना कांग्रेस को बताए चुपचाप सीटों की बंदरबांट कर गए? संप्रग के सबसे बड़े घटक होने के नाते उन्हें कांग्रेस को विश्वास में लेना चाहिए था। उसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने पड़े। कांग्रेस की अपनी ताकत भले सीट जीतने की न हो, किंतु दूसरे को हरवाने की तो है ही। और जहां तक नीतीश कुमार की तारीफ का प्रश्न

है, उसमें किसी तरह की राजनीति नहीं खोजी जानी चाहिए। राजनीति में दोस्ती-दुश्मनी नहीं, पक्षी-प्रतिपक्षी हुआ करते हैं। इसी के बल पर राजनीति चलती भी है। इसलिए सच को सच कहने का साहस तो आपके भीतर होना ही चाहिए। और यदि कोई आपकी या आपके दोस्त की निंदा करता है तो उसे पचाने की ताकत भी होनी चाहिए। राहुल ने नीतीश की तारीफ कर दी, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह उनके दोस्त हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने बांग्लादेश युद्ध में इंदिरा गांधी को दुर्गा कह दिया, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह इंदिरा गांधी के हर काम के प्रशंसक हो गए थे। जब तक राजनेता अपने निहित स्वार्थों से ऊपर नहीं उठेंगे, हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता।